ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 10, Iss 07, 2021

डिजिटल इंडिया और भारत सरकार: सुशासन के सन्दर्भों में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन: चुनौतियाँ एवं सुझाव

डा. पल्लवी सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर,

डी.डी.के.के. (पी.जी.) डिग्री कॉलेज,

चिंगरावठी (बुलन्दशहर)

सारांश

भारत सरकार 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के प्राथमिकता वाला मुद्दा डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती आज के वक्त में है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत ने 8 साल पहले एक फैसला लिया था, जिसकी बदौलत हम आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के चमकते सितारे बन चुके हैं। एक जुलाई 2015 को देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। चीन इस अभियान के माध्यम से सुशासन में पारदर्शिता एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। इस दिशा में भारत सरकार का यह एक उत्तम कदम है।

शब्द कुंजीः डिजिटल इंडिया, सुशासन, ई-गवर्नेस, सशक्त समाज, ज्ञान अर्थव्यवस्था पारदर्शिता, दक्षता, तकनीकी प्रशिक्षण, सार्वभौमिकरण, भागीदारी, कौशल प्रशिक्षण, सतत् विकास, प्रतिबद्धता साइबर सुरक्षा जागरूकता, प्रौद्योगिकी इत्यादि।

परिचयः-

डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश ने विकास के नये चरण पर पग रखा है। यह नवभारत के निर्माण में एक अहम् फैसला हैं। मोदी सरकार ने देश में डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को लांच किया है जिसके माध्यम से सभी कार्यों को 2019 तक कम्प्यूटराइज्ड करना है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करनी है।

किसी भी देश की तरक्की का सूचक सुशासन व्यवस्था हैं। अगर वहाँ सुशासन नहीं तो उस देश की तरक्की अभी सम्भव नहीं है। डिजिटल इंडिया सुशासन व्यवस्था का ही एक भाग है। प्रशासनिक कार्यप्रणाली में डिजिटल इंडिया के माध्यम से अनेक कमियों को दूर किया जा सकता है परन्तु प्रशासनिक कार्यप्रणाली में ई-गवर्नेस तभी सफलतम तरीके से कार्य कर सकती हैं जब तक कि शासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों की कार्यप्रणाली कम्प्यूटरीकृत न कर दी जाये।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 10, Iss 07, 2021

इसमें कोई संदेह नही है कि गाँवों व शहरों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से स्मार्ट बनाया जा सकता है परन्तु इस प्रोजेक्ट के समक्ष अनेकों चुनौतियाँ भी है। आज भी भारत की ग्रामीण आबादी अशिक्षित हैं जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखती, साथ ही सब जगह इंटरनेट ब्रॉडबैंड को पहुँचना दुष्कर काम है, आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ टाॅवर नहीं है। यदि प्रोजेक्ट को सफल बनाना है तो इसके लिए लोगों की पहुँच बुनियादी सुविधाओं तक सुनिश्चित करनी होगी साथ ही लोगों मे इस प्रोजेक्ट के प्रति जागरूकता उत्साह भी बढाया जाना जरूरी है ताकि अधिक से अधिक लोग दैनिक कार्यों में कम्प्यूटर न लैपटॉप, इंटरनेट इत्यादि का इस्तेमाल करें। तभी हम ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जो स्मार्ट दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना हैं। लेकिन इसके विकास व इसको लागू करने में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले तो ऐसा वातावरण बनाना होगा जो डिजिटल इंडिया के लिए आधार प्रदान करें अर्थात् लोगों की मानसिकता ऐसी बनानी होगी जो डिजिटलाइजेशन के अनुकूल हो। इसके लिए सूचना प्रदाताओं को छोटे से छोटे स्तर पर जाकर काम करना होगा ताकि सूचनाओं के स्थानान्तरण में, आँकड़ों की विश्वसनीयता में कमी न आये। इसके लिए इस तकनीकी मे प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी जो इस तकनीकी का इस्तेमाल ठीक प्रकार से कर सके लेकिन भारत में जो लोग सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं वे अभी भी पूरी तरह से इस तकनीकी में प्रशिक्षित नही है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वे ऐसे दफ्तरों में प्रशिक्षित व अनुभवी लोगों को भेजे अथवा ई-गवर्नेस के लिए अलग से डिपार्टमेन्ट की व्यवस्था की जाये जहाँ अनुभवी लोग बैठकर अपना कार्य कर सके।

डिजिटलाइजेशन एक ऐसी औषधि हैं, जो परम्परागत शासन में व्याप्त लगभग सभी बुराईयों को समाप्त कर सकती हैं। यह इसके माध्यम से नागरिकों को सरकारों की सूचनाऐं कहीं भी और कभी भी प्राप्त हो सकती हैं। तेजी से न्याय मिल सकता है।

डिजिटल इंडिया में नौ स्तम्भ सम्मिलित है.

1. ब्राडबेण्ड हाईवे।
2. मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक एक्सेस।
3. जनता इन्टरनेट ऐक्सेस कार्यक्रम।
4. ई-गवर्नेस के जरिये सरकार मे सुधार।
5. ई-क्रान्ति सेवाओं को इलेक्ट्राॅनिक रूप से प्रदान करना।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 10, Iss 07, 2021

6. सभी के लिए सूचनायें।
7. इलैक्ट्रोनिक उत्पादन।
8. नौकरियों के लिए आई टी।
9. जल्दी पैदावार कार्यक्रम।

<u>डिजिटल इंडिया पारदर्शिता और सुशासन में सहायकः-</u>

डिजिटल इंडिया ऐसी योजनाएँ बनाकर सुशासन सुनिश्चित करने का वादा करती है, जो सुशासन की विशेषताओं को लागू करने में मदद करती है। 2014 में 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस मनाने की स्थापना की गई। जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती ही सुशासन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

1. कानून का शासन;
2. पारदर्शिता;
3. जवाबदेही;
4. सामाजिक समानता और समविशन;
5. दक्षता और प्रभावशीलता;
6. भागीदारी।

डिजिटल इंडिया के आने से सरकार से उम्मीद बढ़ गयी है क्योंकि शासन बहुत जटिल हो गया है। डिजिटल इंडिया सुशासन को आगे बढ़ाने में सहायक इसे ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित कर सकता है। ई-गवर्नेंस विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे लेन-देन, पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को लागू करने की प्रक्रिया है। ई-गवर्नेंस के स्तंभ लोग, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संसाधन है। निम्नलिखित की डिजिटलीकरण करके उन्हें मजबूत किया जा सकता है-

ई-लोकतंत्र | डिजिटल के | ई-प्रशासन

ई-सेवाएँ

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी विभिन्न पहल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यदि हर जानकारी आॅनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी तो

IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 10, Iss 07, 2021

इससे पारदर्शिता और जवाबदेहिता अपने आप आ जाएगी। डल ळवअजण् एप्लिकेशन एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहाँ लोग आगे आकर राष्ट्र-निर्माण पर चर्चा कर सकते हैं। नागरिकों को शासन की पहल में शामिल करने का एक मंच है। इन पहलों का उद्देश्य सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

उद्देश्यः-

डिजिटल इंडिया का उद्देश्य देश को डिजिटल-समक्ष समाज में परिवर्तित करना है, जिसे केन्द्र सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सुविधाएँ इलैक्ट्राॅनिक रूप से निवासियों को उपलब्ध हो। यह ग्रामीण लोगों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक देशव्यापी कार्यक्रम है। सशक्त करेन की शक्ति, डिजिटल इंडिया योजना का आदर्श वाक्य है। साइबरस्पेस को सुरक्षित और सुरक्षित बनाना। रूपांतरित डिजिटल सेवा के माध्यम से व्यवसाय करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए।

- डिजिटल साक्षरता का सार्वभौमिकरण।
- नगदीरहित डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना।
- भारत में निर्माण और दुनिया भर में उत्पादों को बेचना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है।
- कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके गरीब लोगों का विकास दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का उद्देश्य है।

डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट नरेन्द्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डिजिटल भारत होने से आम आदमी की जिन्दगी आसान तो होगी लेकिन इसके कुछ व्यावहारिक परेशानियाँ और चुनौतियाँ भी सामने आएंगी। जानियो क्या हैं वह परेशानियाँ एवं चुनौतियाँ।

डिजिटल इंडिया की चुनौतियाँः-

डिजिटल इंडिया के सफल कार्यान्वयन के समक्ष कई बाधाएँ हैं, जैसे-

1. डिजिटल निरक्षरता
2. खराब बुनियादी ढाँचा
3. कम इंटरनेट स्पीड
4. विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 10, Iss 07, 2021

5. काराधान से सम्बन्धित मुद्दे आदि।
6. अन्य विकसित देशों की तुलना में दैनिक इंटरनेट गति साथ ही वाई-फाई हाॅटस्पाॅट धीमी है।
7. अधिकांश छोटे और मध्यम उद्योग की नई आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है।

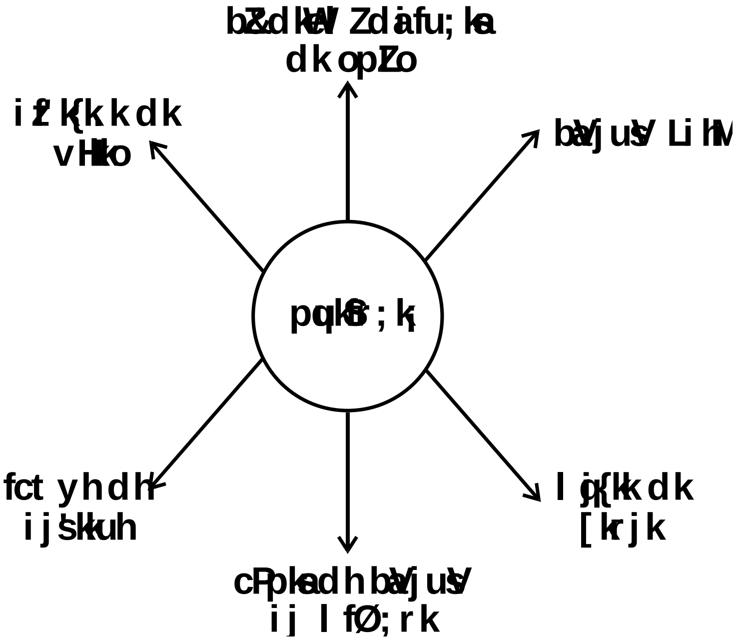

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सुझावः-

डिजिटल साक्षरता नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम हैं लोगों को पता होना चाहिए कि वे अपने डेटा को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना होगा, इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि को बढ़ाने के लिए नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, इंटरनेट सेवाओं के लाभों के बारे में शिक्षित और सूचित करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

डिजिटल इंडिया अभियान अपने आप सफल नहीं हो सकता, डिजिटल इंडिया को हकीकत में बदलने के लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं-

1. डिजिटल विभाजन को संबोधित करने की आवश्यकता है।
2. सामग्री निर्माण सरकार की ताकत नहीं है. इस मिशन के लिए दूरसंचार कंपनियों और अन्य फर्मों के साथ सामग्री और सेवा साझेदारी की आवश्यकता है।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 10, Iss 07, 2021

3. डिजिटल बुनियादी ढांचे के सतत विकास के लिए पीपीपी मॉडल का पता लगाया जाना चाहिए।

4. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतिम छोर तक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल कराधान नीतियां, परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी होनी चाहिए।

5. डिजिटल इंडिया परियोजना की सफलता न्यूनतम साइबर सुरक्षा जोखिमों के साथ अधिकतम कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है। इसके लिए हमें एक मजबूत साइबर अपराध रोधी टीम की आवश्यकता है जो डेटाबेस का रख-रखाव करें और चैबीसों घंटे उसकी सुरक्षा करें।

6. साइबर सुरक्षा में कौशल में सुधार करने के लिए, हमें स्नातक स्तर पर साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन निकायों को विभिन्न कौशल आधारित साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

7. विभिन्न विभागों की प्रभावी भागीदारी तथा मांगपूर्ण प्रतिबद्धता एवं प्रयासों की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नीतियों को इस लक्ष्य का समर्थन करना चाहिए।

8. सफल कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न कानूनों में संशोधन होना चाहिए जो लंबे समय से भारत में प्रौद्योगिकी के विकास में बाधा बने हुए हैं।

lUnHkZ xzUFk lwph%&

1- बेदी और साथी: ‘‘गवर्नमेंट एट नेट’’, ‘‘न्यू गवर्नेन्स अपोच्र्यूनिटी फाॅर इण्डिया’’, सेज पब्लिकेशन-2010

2- कपूर, सी॰ जगदीशः ‘‘आई एण्ड गुड गवर्नेंस’’, इन्डियन जनरल आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाॅल्यूम ग्स्टप्ए छवण्.3, जुलाई-सितम्बर 2000

3- डे॰बी॰के॰: ‘‘ई-गवर्नेस इन इण्डिया प्रोबल्म्स चैलेन्जिंग एण्ड अप्रोच्यूनिटी ए फ्यूचर विजन’’, इण्डियन जनरल आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाॅल्यूम-46, अंक-3, जुलाई-सितम्बर, 2004

4- बिष्ट, दीक्षा: ‘‘भारत में इन्टरनेट का प्रयोग’’, विज्ञान प्रगति, दिसम्बर 2004

5- गुप्ता, एम॰पी॰, कुमार, प्रभात और भट्टाचार्य, जयजीत: ‘‘गवर्नमेन्ट आॅनलाइन अपोरच्यूनिटी एण्ड चैलेन्जिस’’, टाटा एम॰सी॰ ग्रा॰ हिल, न्यू देहली, 2004

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 10, Iss 07, 2021

6- डा॰ देवा, वासू: ‘‘ई-गवर्नेंस इन इण्डिया ए रियलिटी’’, काॅमनवेल्थ प्रकाशन, न्यू दिल्ली, 2005

7- डा॰ अग्रवाल व उमेश चन्द्र: ‘‘भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास: प्रयास एवं सम्भावनाएँ’’, प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2005

8- बावेजा, योगेश: ‘‘डज़ ई-गवर्नेंस मिन्स गुड गवर्नेंस’’, योजना अगस्त 2005

9- एरी विको: ‘‘एण्टीरोइको एण्ड मैन्त्री मैलकिया आॅफ डिजिटल गवर्नमेन्ट’’, आइडिया ग्रुप रिफ्रेन्स, टेरो, लन्दन मेलबन, सिंगापुर, वाॅल्यूम-प्प्प्, 2007

10- अग्रवाल, एस॰ सतीश: ‘‘एम्पाॅवरमेन्ट एण्ड सोशल गवर्नेंस’’, ईशा बुक्स, देहली 2010

11- बंसल, एस॰के॰: ‘‘साइबर मिलेनियम चैलेन्जिस एण्ड अपोरच्यूनिटी’’, ए॰पी॰एच॰ पब्लिक कारपोरेशन, न्यू दिल्ली 2010

12- इन्डिया करप्शन स्टडी टू इम्प्रूव गवर्नेंस, नई दिल्ली, सेन्टर फाॅर मीडिया स्टडी.